ग्रामीण लोहरदगा

वर्ष – 1
अंक – 7

http:\\www.rural.nic.in, http:\\lohardaga.nic.in एवं http:\\www.jharkhandonline.gov.in पर भी उपलब्ध

जिला ग्रामीण विकास अभिकरण, लोहरदगा द्वारा प्रकाशित मासिक समाचार पत्र

जुलाई 2006

अपनी बात

केन्द्र एवं राज्य सरकार के विभिन्न योजनाओं के सफल क्रियान्वयन के साथ–साथ कृषि, वानिकी एवं बागवानी के क्षेत्र में उत्तरोत्तर वृद्धि हेतु लोहरदगा जिला प्रशासन कृत संकल्पित है। वर्षा ऋतु में राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना के तहत रोजगार सृजन की निरंतरता को बनाये रखने तथा कृषि क्षेत्र में वानिकी एवं बागवानी के विकास हेतु वृहद पैमाने पर सामाजिक वानिकी का कार्य लिया गया है। वन विभाग के सहयोग से किस्को एवं सेन्हा में 284 हेक्टेयर वन भूमि तथा 95 हेक्टेयर जंगल झाड के रूप में दर्ज सरकारी भूमि पर वन सुरक्षा समितियों द्वारा एन.आर.ई.जी.एस. के तहत गम्हार, एकासिया इत्यादि वृक्षारोपण किया जा रहा है।

जिले में व्यवसायिक तथा नगदी फसलों की खेती को प्रोत्साहित करने के साथ–साथ औषधीय वृक्षारोपण के तहत 14 एकड़ में स्टीविया तथा 20 एकड़ में सफेद मूसली एवं 20 एकड़ में पर्यावरणीय दृष्टिकोण से लाभकारी जेट्रोफा की खेती की जा रही है। राष्ट्रीय सम विकास योजना के तहत भंडरा प्रखण्ड के जमगाई गाँव मे 16 हेक्टेयर भूमि पर 48000 अर्जुन का वृक्षारोपण किया जा रहा है। कुडू प्रखण्ड के ग्राम जरियो के 7 एकड़, चिरी के 6 एकड़ तथा लोहरदगा प्रखण्ड के ग्राम बरटपुर के 7 एकड़ कुल 20 एकड़ पर दिव्य औषधि सफेद मूसली की खेती की जा रही है। लोहरदगा के बराटपुर एवं सेन्हा के बबू तथा बरही के कुल 14 एकड़ भूमि पर औषधीय स्टीविया की खेती की जा रही है। 60 एकड़ में मद्रासी ओल ,70 एकड़ में अदरख, 5 एकड़ में टी.पी.एस. आलु तथा 50 एकड़ में नेपियर/बर्सीन घास (चारा उत्पादन) की खेती की जा रही है।

राष्ट्रीय बागवानी मिशन के अन्तर्गत लोहरदगा जिला का चयन किया गया है एवं इसके अन्तर्गत विकास भारती विशुनपुर के द्वारा 300 हेक्टेयर में आम–लीची, 300 हेक्टेयर में पपीता, 75 हेक्टेयर में अदरख एवं 75 हेक्टेयर में हल्दी की खेती की जा रही है। इसके अन्तर्गत वर्ष 2005–06 हेतु वृक्षारोपण का शुभारंभ कुडू प्रखण्ड के टाटी गाँव में दिनांक 13 जुलाई 06 को माननीय मुख्य सचिव, झारखंड सरकार द्वारा किया गया।

अब तक बागवानी के क्षेत्र में किये गये कार्यों को और अधिक आयाम देने हेतु जिला प्रशासन के द्वारा व्यापक पैमाने पर ग्रामीणों को जागरूक करने का कार्य किया जा रहा है। आगामी माह में राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना के अन्तर्गत जिले के 352 गाँवों में योजना के प्रचार प्रसार एवं अवशिष्ट मजदूरों के पंजीकरण के लिये एन.आर.ई.जी.एस. पखवाड़ा का आयोजन किया जाएगा जिसमें एन.आर.ई.जी.एस. के साथ–साथ सामाजिक वानिकी को प्रश्रय देने हेतु ग्रामीणों को प्रेरित किया जाएगा।

कृषि के साथ–साथ बागवानी के विकास के लिये सिंचाई सुविधा की उपलब्धता अपरिहार्य है। जिले में व्यापक पैमाने पर चलाये गये सिंचाई योजनाओं ने जिले का सिंचित क्षेत्र लगभग 16 प्रतिशत तक पहुँचाया है। कृषि, उद्यान, सहकारिता विभागों के पारस्परिक समन्वय एवं गैर सरकारी संस्थाओं की सहभागिता ने जिले में बागवानी के उन्नत भविष्य की ओर संकेत किया है। वर्तमान में जिले की कुल कृषि योग्य भूमि का 8–9 प्रतिशत भाग में ही बागवानी किया जा रहा था जबकि कुल कृषि योग्य भूमि के दो तिहाई भाग में बागवानी की संभावनाएँ आँकी गई है। भविष्य की संकल्पनाओं को अमलीजामा पहनाने हेतु ग्रामीणों के आत्मविश्वास को मजबूत करने तथा उन्हें पारंपरिक कृषि के अलावे औषधीय, पर्यावरणीय दृष्टिकोण से लाभकारी पौधों, नगदी फसलों की खेती के लिये प्रेरित करने के साथ–साथ उन्हें आवश्यक सुविधाएँ मुहैया कराने की आवश्यकता है। जिला प्रशासन, लोहरदगा जिला को बागवानी के क्षेत्र में राज्य का अग्रणी जिला बनाने के लिये कृत संकल्पित है। इस स्वप्न को साकार करने के लिये आम जनों विशेषकर प्रगतिशील कृषकों को आगे आने की जरूरत है।

आराधना पटनायक
उपायुक्त, लोहरदगा

माननीय मुख्य सचिव ने राष्ट्रीय बागवानी मिशन के अन्तर्गत वृक्षारोपण कार्यक्रम का शुभारंभ किया

लोहरदगा जिले के कुडू प्रखण्ड के टाटी गांव में राष्ट्रीय बागवानी मिशन के अन्तर्गत वृक्षारोपण कार्य का शुभारंभ 13 जुलाई 2006 को झारखंड राज्य के मुख्य सचिव श्री एम. के. मंडल के द्वारा किया गया। गोधुलि बेला में माननीय मुख्य सचिव ने उपस्थित लोगों को संबोधित करते हुए राष्ट्रीय बागवानी मिशन के अन्तर्गत किये जा रहे कार्यों की जानकारी दी। गैर सरकारी संस्था विकास भारती विशुनपुर द्वारा आयोजित इस कार्यक्रम में जिले की उपायुक्त श्रीमती आराधना पटनायक, पुलिस अधीक्षक श्री मनोज कौशिक, उपविकास आयुक्त श्री बी.के. मुण्डा, अनुमण्डल पदाधिकारी श्री महेशचंद्र पंडा, प्रखण्ड विकास पदाधिकारी, श्री संजय पी. एम. कुजूर, अंचलाधिकारी श्री अरूण कुमार खलखो समेत विकास भारती के श्री अशोक भगत, कमलाकांत पाण्डेय, भिखारी भगत, विकास सिंह और काफी संख्या में ग्रामीण उपस्थित थे। इस अवसर पर फलदार वृक्ष के पौधे लगाये गये। मुख्य सचिव ने कहा कि जिले में शीघ्र ही 180 एकड़ भूमि में फलदार पौधे लगाये जाएंगे। उन्होंने लोहरदगा के कृषकों के उत्साह की सराहना की। मुख्य सचिव ने किसानों का आह्वान किया कि वे व्यक्तिगत एवं प्रदेश की समृद्धि के लिए अधिक से अधिक फलदार वृक्ष लगाएं।

उपायुक्त श्रीमती आराधना पटनायक ने फूलों, फलदार वृक्षों एवं औषधीय पौधों की खेती कर किसानों को आत्मनिर्भर बनने की सलाह दी। उन्होंने बाजार की मांग के अनुसार व्यक्तिगत निजी जमीन पर भी बागवानी करने की प्रेरणा दी। विकास भारती के सचिव अशोक भगत ने संस्था द्वारा राष्ट्रीय बागवानी मिशन के तहत् राज्य के दस जिलों में फलदार वृक्षारोपण कार्यक्रम चलाने की जानकारी दी।

भंडरा प्रखण्ड के मलंगटोली गाँव में फलदार वृक्षारोपण अभियान की शुरूआत 14 जुलाई 2006 को उपायुक्त के द्वारा की गई। स्वयं सेवी संस्था, विकास भारती, विशुनपुर द्वारा आयोजित इस कार्यक्रम में कई पौधे लगाये गये। इस अवसर पर उपस्थित ग्रामीणों को सम्बोधित करते हुए उपायुक्त ने कहा कि फलदार पौधों की खेती कर आर्थिक रूप से आत्मनिर्भर बना जा सकता है। फलदार पौधों को बेहतर देखभाल करने की जरूरत है।

वृक्षारोपण के कार्यक्रम के पश्चात उपायुक्त एवं अन्य वरीय पदाधिकारियों के द्वारा भण्डरा में पंचायत मंडप भवन निर्माण, कोटा में तालाब, गार्डवाल, यात्री शेड निर्माण, ग्रेड 1 पथ, कचमची में आर.ई.ओ. पथ से भीठा चीनी टोंगरी तक ग्रेड ।। पथ निर्माण, कुन्दों में गार्डवाल निर्माण, जमगाई में विधायक मद से निर्माणाधीन सामुदायिक भवन, बी.पी.डी.पी. पथ में ग्रेड ।। पथ निर्माण, नाली निर्माण, भीठा विद्यालय में कीचन शेड, नाली निर्माण आदि कार्यों का भी निरीक्षण किया गया। साथ ही साथ विद्यालयों में शिक्षक–छात्रों की उपस्थिति , मध्याह्न भोजन योजना की स्थिति आदि की भी जानकारी ली गई। योजना कार्यों को मानक गुणवत्ता के साथ ससमय पूरा करने का निर्देश उपस्थित तकनीकी पदाधिकारियों को दिया गया।

योजना आयोग की समीक्षात्मक बैठक में उपायुक्त, लोहरदगा ने प्रेजेंटेशन दिया

योजना आयोग के सदस्य प्रो0 अभिजीत सेन के द्वारा 15 जुलाई 2006 को केन्द्र प्रायोजित योजनाओं की प्रगति की समीक्षा राज्य की राजधानी राँची में की गई। योजना आयोग के दल के साथ राज्य सरकार के विभागीय प्रमुखों की हुई बैठक में सूचना तकनीक, उर्जा, ग्रामीण विकास, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण, मानव संसाधन तथा जल संसाधन विभाग की समीक्षा की गयी।

इस अवसर पर जिले की उपायुक्त श्रीमती आराधना पटनायक के द्वारा योजना आयोग के दल के समक्ष जिले के विकास को प्रतिबिंबित करती हुई दो सफलता की कहानी एवं आदिम जनजातियों के उत्थान हेतु जिला प्रशासन द्वारा किये जा रहे प्रयासों के संबंध में प्रेजेंटेशन दिया गया। लोहरदगा में श्वेत क्रांति तथा मुर्गीपालन व्यवसाय की सफलता ने किस प्रकार ग्रामीण आबादी को आत्मनिर्भर बनाया है, इसका वर्णन उक्त सफलता की कहानी में किया गया है।

विकास कार्यों के निरीक्षण के क्रम में जिला प्रशासन सेन्हा प्रखण्ड सुदूर क्षेत्रों में पहुँचा

लोहरदगा जिला के सेन्हा प्रखण्ड का चापरोंग गाँव जिला मुख्यालय से लगभग 60 कि.मी. की दूरी पर लोहरदगा और गुमला जिले के सीमान्त क्षेत्र में अवस्थित है। 22 जुलाई 2006 को उपायुक्त श्रीमती आराधना पटनायक के नेतृत्व में जिले के प्रशासनिक एवं तकनीकी पदाधिकारियों का एक दल अपने नियमित निरीक्षण के क्रम में चापरोंग गाँव पहुँचा।

प्रशासनिक पदाधिकारियों को अपने घर में पाकर ग्रामीणों का उत्साह देखते बनता था। जिला प्रशासन के दल ने ग्रामीणों के साथ चटाई पर बैठकर मिटिंग की और ग्रामीणों को ग्रामीण विकास विभागीय एवं अन्य लाभकारी योजनाओं के प्रावधानों से अवगत कराया।

घनघोर वन एवं निर्जन रास्तों से गुजरते हुए कई स्थानों पर जिला प्रशासन के दल को रास्ते की दुर्गमता का सामना करना पड़ा। गाड़ियों के दलदली रास्तों में फंस जाने के कारण लगभग 5 किमी कीचड़ वाली रास्तों से पैदल चलकर अधिकारी चापरोंग गाँव के ग्रामीणों के पास पहुचे। चापरोंग गाँव सेन्हा प्रखण्ड के चापरोंग पंचायत के अन्तर्गत है। इस गाँव की कुल आबादी 199 है जिसमें 175 अनुसूचित जनजाति एवं 24 अन्य जाति के लोग हैं। अनुसूचित जनजातियों में भी आदिम जनजाति असुर की प्रधानता है। 95 पुरुषों के विरुद्ध 104 स्त्रियों की आबादी वाले इस गाँव में विद्यालय, आंगनबाड़ी केन्द्र और स्वास्थ्य उपकेन्द्र भी है। ग्रामीणों के निर्मल हृदय से निकले स्वागत गीत एवं उल्लास से युक्त आदिम जनजातियों के स्वागत नृत्य ने यात्रा की परेशानियों को दूर कर दिया। चापरोंग प्राथमिक विद्यालय के अन्दर और बाहर स्थानीय ग्रामीणों के अलावे आसपास के ग्रामीण भी काफी संख्या में

उपस्थित थे। उपायुक्त, लोहरदगा ने उपस्थित ग्रामीणों को राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना, मुख्यमंत्री जननी शिशु एवं मातृ स्वास्थ्य योजना, राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन, राष्ट्रीय बागवानी मिशन, ग्रामीण विद्युतीकरण, शिक्षा, साक्षरता, मध्याह्न भोजन योजना, अपारंपरिक उर्जा श्रोतों के उपयोगों के फायदे, आंगनबाड़ी केन्द्रों में खिचड़ी योजना की शुरूआत, फसल बीमा योजना आदि के प्रावधानों के बारे में विस्तार से जानकारी दी। बैठक में उपस्थित ग्रामीण के द्वारा एक एकड़ जमीन दान दिये जाने के प्रस्ताव दिये जाने पर उपायुक्त के द्वारा पुराने विद्यालय भवन के स्थान पर नये विद्यालय भवन निर्माण योजना की भी स्वीकृति दी गई। इसके अलावे आदिम जनजातियों के लिए बकरी पालन, ओल उत्पादन, वृद्धावस्था पेंशन समेत कई योजनाओं की भी स्वीकृति प्रदान की गई। लौटने के क्रम में रास्ते में कल्याण विभाग द्वारा तुईमूपाट में संचालित जनजातीय आवासीय विद्यालय छात्रावास का भी निरीक्षण उपायुक्त ने किया।

बैठक में काफी संख्या में ग्रामीणों के अलावा उप विकास आयुक्त, अपर समाहर्त्ता, निदेशक, जिला ग्रामीण विकास अभिकरण, परियोजना पदाधिकारी, मेसो क्षेत्र, जिला शिक्षा अधीक्षक, कार्यपालक अभियन्ता, लघु सिंचाई प्रमण्डल, कार्यपालक अभियन्ता, एन.आर.ई.पी., कार्यपालक अभियन्ता, ग्रामीण विकास विशेष प्रमण्डल, जिला उद्यान पदाधिकारी, प्रखण्ड

लोहरदगा जिले में अब तक 18166 निर्धन परिवारों को आवास मुहैया कराया गया

लोहरदगा जिले में अब तक विभिन्न ग्रामीण आवास योजनाओं के अन्तर्गत 18166 निर्धन परिवारों को आवास मुहैया कराया जा चुका है। प्रारंभ से अब तक 14149 व्यक्तियों को इन्दिरा आवास योजना के अन्तर्गत, 2686 व्यक्तियों को बुनियादी न्यूनतम सेवा संवर्द्धन आवास योजना के अन्तर्गत, प्रधानमंत्री आवास योजना के अन्तर्गत 483 व्यक्तियों को तथा 1348 व्यक्तियों को दीन दयाल आवास योजना के अन्तर्गत आवास मुहैया कराया जा चुका है।

वित्तीय वर्ष 2006–07 के लिये जिले को प्राप्त कुल लक्ष्य के अनुसार प्रखण्डवार लक्ष्य निम्न प्रकार लिया गया है :–

क्र.	प्रखण्ड का नाम	01.04.2006 को निर्माणाधीन आवास	2006–07 में प्राप्त लक्ष्य	कुल
1	लोहरदगा	28	100	128
2	सेन्हा	64	112	176
3	कुड़ू	28	147	175
4	किस्को	33	101	134
5	भंडरा	37	98	135
	कुल	190	558	748

जिले को चालु वित्तीय वर्ष में प्रथम किस्त का आबंटन प्राप्त हो चुका है। निर्माणाधीन आवासों को पूर्ण किया जा रहा है।

आंगनबाड़ी केन्द्रों में पोषाहार के रूप में सत्तु–मुढ़ी के स्थान पर खिचड़ी देने की योजना प्रारंभ

समेकित बाल विकास परियोजना के अन्तर्गत अब तक आगंनबाड़ी केन्द्रों में पोषाहार के रूप में सत्तु–मुढ़ी का वितरण किया जाता था। सरकार के द्वारा बनायी गई योजना के अनुसार आगंनबाड़ी केन्द्रों में अब पोषाहार के रूप में खिचड़ी भोजन का वितरण किया जाना है। पूर्व में जिले के दो प्रखण्डों कुड़ू एवं भंडरा में यह योजना गत वर्ष सितम्बर माह से ही लागू की जा चुकी है। जिले के तीन प्रखण्डों लोहरदगा सदर, सेन्हा व किस्को प्रखण्ड में खिचड़ी पोषाहार का वितरण कार्यक्रम का शुभारंभ जिले की उपायुक्त श्रीमती आराधना पटनायक के द्वारा 1 जुलाई को किया गया। इस प्रकार जिले के सभी 511 आगंनबाड़ी केन्द्रों में यह कार्यक्रम लागू किया जा चुका है। इस कार्यक्रम के अन्तर्गत 3–6 वर्ष के बच्चों को पौष्टिक आहार के रूप में खिचड़ी दी जायेगी। 0–3 वर्ष के बच्चों, किशोरी, बालिका व धात्री माता के लिए 25 दिनों के लिये चावल, दाल व मसाला दिया जाएगा। पहले अनाज का वितरण माह में एक बार किया जाता था परन्तु अब वितरण दो से तीन बार में किया जाएगा।

सदर प्रखण्ड के जुरिया बड़काटोली आंगनबाड़ी केन्द्र पर बच्चों को पोषाहार के रूप में खिचड़ी खिलाकर कार्यकम का शुभारम्भ करते हुये उपस्थित माताओं को उपायुक्त ने सम्बोधित किया। अपने सम्बोधन में गांव में साफ–सफाई रखने, गांव के माहौल को स्वास्थ्वर्द्धक बनाने तथा आगंनबाड़ी केन्द्रों को आदर्श केन्द्र बनाने की अपील की। उन्होंने कहा कि बच्चों के सम्पूर्ण विकास के लिए भोजन के साथ साथ स्वस्थ एवं स्वच्छ वातावरण भी जरूरी है। उन्होंने पोषाहार की पौष्टिक एवं रूचिकर बनाये रखने के लिए उपमा, हलवा, दाल, चावल, सब्जी आदि विविध व्यंजन देने के प्रावधान की भी जानकारी ग्रामीणों को दी। इस अवसर पर ग्रामीणों से फलदार व उपयोगी वृक्षों को लगाने की भी अपील की।

राष्ट्रीय बागवानी मिशन की बैठक में वृक्षारोपण कार्य में तेजी लाने का निर्देश

राष्ट्रीय बागवानी मिशन की बैठक 5 जुलाई 2006 को समाहरणालय में उपायुक्त की अध्यक्षता में सम्पन्न हुई। जिला उद्यान पदाधिकारी द्वारा जानकारी दी गई कि बागवानी मिशन के तहत लोहरदगा जिले में विकास भारती, बिशुनपुर का चयन सरकार द्वारा किया गया है। वृक्षारोपण के लिये गड्ढों की खुदाई का काम तेजी से किया जा रहा है। 2005–06 के लिए निर्धारित लक्ष्य के अनुरूप आम, अमरूद, लीची आदि लगाने का कार्य एक सप्ताह के अन्दर समाप्त किये जाने की आशा है। बैठक में वित्तीय वर्ष 2006–07 के लिए वार्षिक कार्य योजना भी प्रस्तुत की गई। इस कार्ययोजना पर स्टैंडिंग कमेटी की बैठक में अनुमोदन कराने के बाद विचार किया जाएगा। उपायुक्त ने 7 जुलाई से 15 जुलाई के अन्दर वृक्षारोपण कार्य को सम्पन्न कराने का निर्देश दिया।

ग्रामीण विकास विभाग, भारत सरकार के निदेशक के द्वारा सम्पूर्ण स्वच्छता अभियान कार्यक्रमों का निरीक्षण

श्री संजय कुमार राकेश, निदेशक, ग्रामीण विकास विभाग, भारत सरकार ने 21 जुलाई 06 को

जिले के भण्डरा प्रखण्ड अन्तर्गत उल्टी ग्राम में सम्पूर्ण स्वच्छता अभियान के तहत चलाये जा रहे कार्यक्रमों का गहन निरीक्षण किया। उल्टी ग्राम एक जनजातीय बहुल ग्राम है। इस गाँव के 66 घरों में से अबतक 48 घरों में शौचालय का निर्माण कराया जा चुका है। इस गाँव में सम्पूर्ण स्वच्छता अभियान का कार्यान्वयन स्वयं सेवी संस्था, लोहरदगा ग्राम स्वराज संस्थान के माध्यम से कराया जा रहा है।

अपने निरीक्षण के क्रम में केन्द्रीय निदेशक ने लाभुकों से बातचीत की एवं निर्माण किये गये शौचालयों का निरीक्षण किया। लाभुकों को स्वच्छता के संबंध में जिला स्तर से दिये गये जानकारी

एवं प्रशिक्षण की भी जानकारी ली। भारत सरकार के प्रतिनिधि ने ग्रामीणों से पानी उबाल कर पीने एवं स्वच्छता के मानकों का पालन करने का आह्वान किया। निरीक्षण के समय जिले की उपायुक्त श्रीमती आराधना पटनायक, उप विकास आयुक्त श्री ब्रज किशोर मुण्डा, निदेशक, लेखा प्रशासन श्री श्रवण साय के साथ अन्य पदाधिकारी भी उपस्थित थे।

अवशिष्ट निरक्षरता उन्मूलन कार्यक्रम 26 जनवरी 07 तक पूर्ण करने का लक्ष्य

नव विहान जिला साक्षरता समिति के द्वारा जिले में चलाये जा रहे अवशिष्ट निरक्षरता उन्मूलन कार्यक्रम की रूप रेखा की समीक्षा हेतु उपायुक्त श्रीमती आराधना पटनायक की अध्यक्षता में 1 जुलाई 06 को सम्पन्न बैठक में जिले में उत्तर साक्षरता कार्यक्रम एवं

सम्पूर्ण साक्षरता कार्यक्रम में छूटे हुए निरक्षरों को अवशिष्ट निरक्षरता उन्मूलन कार्यक्रम के अन्तर्गत आच्छादित कर साक्षर बनाने के संबंध में विचार विमर्श किया गया। इसके लिए आवश्यक साक्षरता केन्द्रों की स्थापना करने की आवश्यकता पर बल दिया गया।

वैसे गांव जहां के लोग अब भी जागरूक नहीं हुए हैं, उन गांवों में विशेष ध्यान देने का निदेश दिया गया। अवशिष्ट निरक्षरता उन्मूलन कार्यक्रम के तहत साक्षरता केन्द्रों का संचालन 15 अगस्त 2006 से प्रारंभ कर कर दिया गया है। इस कार्यक्रम को 26 जनवरी 2007 तक पूरा करने का लक्ष्य लिया गया है।

सफलता की कहानी - 3

वर्मी कम्पोस्ट उत्पादन से दिखायी स्वरोजगार की राह

लोहरदगा प्रखण्ड का कैमो गाँव लोहरदगा शहर के निकट बसा एक जनजाति बहुल गाँव है। इस गाँव की जनसंख्या 1322 है जिसमें 74 प्रतिशत अनुसूचित जनजाति है। इस गाँव की अधिकांश जनसंख्या जीविकोपार्जन हेतु कृषि पर निर्भर है। गैर कृषि मौसम में गाँव के महिला पुरूष निकटवर्ती शहरी क्षेत्र में मजदूरी का काम करते हैं। इस गाँव की निशी महिला मंडल ने अपने मेहनत और दृढ़ संकल्प के कारण गाँव ही नहीं वरन् जिले की महिला संगठनों के लिये एक मिसाल बन गयी है।

वर्ष 2002 तक गाँव की महिलाएँ रोजगार की तलाश में जिला से पलायन कर जाती थीं। रोजगार की तलाश में ईंटा भट्ठा को

प्राथमिकता देना उनकी मजबूरी नहीं वरन् उनकी आदतों में शुमार थीं। वर्ष 2002 के आरंभिक माहों में गाँव की कुछ महिलाओं ने गैर सरकारी संगठन लोहरदगा ग्राम स्वराज संस्थान की प्रेरणा के फलस्वरूप गाँव में ही रहकर रोजगार करने की ठानी। दस महिलाओं ने 17 मई 2002 को निशी महिला मंडल का गठन किया। निशी गाँव का एक बच्चा है जिसके नाम पर महिला मंडल का नामकरण इसलिये किया गया

ताकि गाँव के लोगों को महिला मंडल का नाम आसानी से याद रहे। उन दिनों महिला मंडल के सदस्य सप्ताह में 2 रू0 जमा करते थे। कुछ सदस्य स्थानीय रेजा का काम करती थी जबकि कुछ सब्जी का क्रय – विक्रय कर जीवन निर्वाह करती थीं।

महिला मंडल बन जाने के बाद महिलाओं ने उत्साह में 5 रू0 प्रति सप्ताह जमा करने लगीं। इस राशि का उपयोग सामुदायिक कार्यों के लिये भी किया जाता था। बीमारी, शादी एवं इसी तरह के अन्य अवसरों पर सदस्य ऋण ले सकते थे। महिला मंडल के सदस्यों ने 2003 से कैमोलेक का उत्पादन आरंभ किया। कैमोलेक हारलिक्स या सेरेलेक जैसा एक अतिरिक्त खाद्य पदार्थ है जिसे कमजोर महिला या बच्चे के लिये गाँव में उपयोग किया जाता है। गेहूँ, मकई चना, मूँगफली, मडुवा, जौ, को अलग–अलग साफ करने के बाद भींगाकर अंकूरित करने के पश्चात भून कर पीसा जाता है। अन्त में घी और अल्प मात्रा में चीनी डालकर सेरेलेक के जैसा बनाकर डिब्बों में बंद कर 52 रू0 प्रति किलो की दर से बेचा जाता है। कैमोलेक को निकटवर्ती जिला गुमला में भी भेजा जाता रहा है। अब भी कैमोलक का उत्पादन किया जा रहा है।

निशी महिला मंडल को 2004 में स्वर्णजयंती ग्रामीण स्वरोजगार से जोड़ा गया और 10000 रू0 की राशि प्रथम किस्त के रूप में दी गई। उक्त राशि से महिला मंडल ने टमाटर की खेती की और लाभ कमाकर ऋण के रूप में ली गई राशि 6 माह के अन्दर ही बैंक को लौटा दी। अगले मौसम में फूलगोभी, ईख, गेहूँ की खेती कर महिला मंडल ने आर्थिक रूप से अपने को मजबूत किया। ग्रेडिंग के पश्चात इस महिला मंडल को 3,56,050.00 रू0 परिक्रामी निधि के रूप में 2004 के अक्टूबर माह में मिला। इस राशि का 50 प्रतिशत अनुदान तथा 50 प्रतिशत ऋण के रूप में उपलब्ध

कराया गया था। महिला मंडल के सदस्यों ने वर्मी कम्पोस्ट अर्थात केंचुआ खाद के उत्पादन का प्रशिक्षण लिया और केंचुआ खाद का उत्पादन कार्य प्रारंभ किया। 10 बेड तैयार किये गये। एक बेड में 50000 केंचुआ उत्पादित किये गये। अब तक 6000 किलोग्राम केंचुआ खाद का विक्रय 5 रू0 प्रति किलो की दर से किया जा चुका है। महिला मंडल ने औषधीय पौधों की खेती भी प्रारंभ की। 50 डिसमिल जमीन पर

सफेद मूसली तथा 50 डिसमिल पर सतावर की खेती प्रारंभ की गई। 178 किलो सफेद मूसली तथा 4000 पौधा सतावर के लगाये गये। अब तक 150 किलो सफेद मूसली बेचा जा चुका है। 10 किलो सफेद मूसली कैमोलेक में मिलाया गया है तथा 30 किलो बीज के रूप में गाँव के अन्य किसानों को खेती के लिये दिया गया है।

महिला मंडल को उपलब्ध करायी गई राशि का ऋण अंश की राशि तीन साल में चुकायी जानी थी परन्तु महिला मंडल के सदस्यों ने निर्णय लिया है कि वर्मी कम्पोस्ट तथा सफेद मूसली के विक्रय से ऋण

चुकाने लायक राशि उपलब्ध हो गई है अतः ऋण की राशि आगामी अगस्त 06 के अंत तक चुका दी जाएगी। महिला मंडल के सदस्यों के सभी बच्चे स्कूल जाते हैं। पुस्तक एवं अन्य विशेष खर्चों के लिये उन्हें किसी पर निर्भर रहने की जरूरत नहीं है। महिला मंडल ने गाँव की अन्य महिलाओं को भी केंचुआ खाद के उत्पादन कर प्रशिक्षण दिया है। वे भी अब केंचुआ खाद के उत्पादन के लिये तैयार हो रही हैं।

कैमो गाँव के तालाब के बगल से एक मिट्टी मोरम पथ का कार्यान्वयन भी महिला मंडल के सदस्यों की सहभागिता से किया जा रहा है। महिला मंडल की अध्यक्ष तारा देवी, सचिव बिराज देवी, कोषाध्यक्ष हेमंती देवी एवं अन्य सदस्य मंगिया देवी, मिनसरिया देवी, बुलु देवी, रूपैण देवी, बुतरू देवी, बुदो देवी एवं परदेशिया देवी ने तमाम रूढ़ियों को दरकिनार कर महिला सशक्तिकरण की अनूठी मिसाल कायम की है। इस महिला मंडल ने अपनी सफलता से रोजगार के लिये गाँव से पलायन को झुठला दिया है।

स्वजलधारा योजना पर एक दिवसीय कार्यशाला का आयोजन

सम्पूर्ण स्वच्छता अभियान के तहत पाण्डेय गणपत राय भवन में 08 जुलाई 2006 को स्वजलधारा योजना पर एक दिवसीय कार्यशाला का उद्घाटन उपायुक्त श्रीमती आराधना पटनायक के द्वारा किया गया। कार्यशाला में स्वजलधारा योजना की विस्तृत जानकारी ग्राम जल एवं स्वच्छता समिति के अध्यक्ष, सचिव, जिले के सभी प्रखण्डों के पंचायत समन्वयकों एवं कलस्टर समन्वयकों को दी गई। स्वजलधारा के अन्तर्गत ग्रामों में स्वच्छ जल उपलब्ध कराने हेतु 14 योजनाएँ ली जा रही हैं। यह योजना पूरी तरह से सामुदायिक है। इसके अन्तर्गत ग्रामीणों की एक समिति गठित की जाएगी जिसके देखरेख में योजना का कार्यान्वयन किया जाएगा।

सम्पूर्ण स्वच्छता अभियान की प्रगति की समीक्षा की गई

सम्पूर्ण स्वच्छता अभियान प्रकल्प के कार्यो की प्रगति की समीक्षा हेतु 04.07.2006 को संबंधित अधिकारियों और स्वयं सेवी संगठनों के प्रतिनिधियों की एक समीक्षात्मक बैठक उपायुक्त की अध्यक्षता में सम्पन्न

हुई। बैठक में निर्धारित समय–सीमा के अन्दर जिले के सभी गाँवों में कम लागत वाले शौचालय का निर्माण कार्य प्राथमिकता के आधार पर पूर्ण कराने का निदेश उपायुक्त के द्वारा दिया गया । समिति को अवगत कराया गया कि प्रथम चरण में 100 शौचालयों का निर्माण आंगनबाड़ी केन्द्रों में कराया जा रहा है। विद्यालयों में शौचालय निर्माण की समीक्षा के क्रम में इस कार्य को द्रुत गति से पूरा करने के लिए जिला शिक्षा अधीक्षक को निर्देश दिये गये। बैठक में स्वच्छता के अलावे स्वजलधारा योजना के कार्यान्वयन पर भी चर्चा की गयी। स्वजलधारा के लिए 14 समितियां बनायी जा चुकी है। इस योजना पर शीघ्र कार्य शुरू करने का निर्देश दिया गया।

विश्व स्तनपान सप्ताह के आयोजन को सफल करने हेतु बैठक का आयोजन

1 अगस्त 2006 से 7 अगस्त 2006 तक विश्व स्तनपान सप्ताह के आयोजन को सफलीभूत करने हेतु जिले की उपायुक्त श्रीमती आराधना पटनायक की अध्यक्षता में जिला स्तर पर 28 जुलाई 06 को एक बैठक सम्पन्न हुई। बैठक में स्तनपान सप्ताह के कार्यक्रम को ग्राम्य स्तर से आरंभ करने का निर्णय लिया गया। बैठक में

जानकारी दी गई कि इस वर्ष आई.एम.एस. के द्वारा मां के दूध का विकल्प नहीं को उद्देश्य वाक्य के रूप में लिया गया है। कार्यक्रम को सफल बनाने के लिये बाल विकास परियोजना पदाधिकारी, आँगनबाड़ी सेविकाओं, सहायिकाओं, स्वास्थ्य कर्मियों के साथ साथ आम जनता को भी इस कार्यक्रम से जोड़ने का निर्णय लिया गया। तय किया गया कि 1 से 4 अगस्त तक जिले के 78 आंगनबाड़ी कलस्टरों में , 5 से 6 अगस्त को प्रखण्ड स्तर पर तथा 7 को समापन समारोह जिला स्तर आयोजित किया जाएगा। यह भी निर्णय लिया गया कि कार्यक्रमों में नियमित टीकाकरण और स्तनपान कराने वाली माता को बेस्ट मदर का सम्मान दिया जाएगा। पोस्टर, स्लोगन, क्विज, चित्राकला, भाषण आदि प्रतियोगिताओं के द्वारा स्तनपान सप्ताह कार्यक्रम को व्यापक रूप से प्रचारित करते हुये इसके साथ परिवार कल्याण कार्यक्रम को भी जोड़ने का निर्णय लिया गया। बैठक में

सिविल सर्जन डा. आर.पी. सिंह, परियोजना पदाधिकारी, श्री बसंत कुमार सुरीन, जिला प्रोग्राम अधिकारी श्री प्रदीप किण्डो, डीपीआरओ, माकिरण मुण्डा, केयर के अधिकारी सुधीर दास, बाल विकास परियोजना पदाधिकारियों के अलावे स्वयं सेवी संस्थाओं के प्रतिनिधि भी उपस्थित थे।

लोहरदगा के पर्यटन स्थल-7

कोराम्बे स्थित चौकी से आठवीं सदी के अन्तराल में पाया जाने वाला सती स्टोन। कोराम्बे की प्राचीनता को प्रमाणित करता प्रागैतिहासिक चिन्ह।

जिला मुख्यालय से लगभग 35 किलोमीटर की दूरी पर सेन्हा प्रखण्ड में अवस्थित प्राचीन मंदिर में महामाया मां की प्रतिमा। पर्वतीय गुफा व प्राचीन तालाब अपनी ऐतिहासिक विशेषताओं के लिए आकर्षण का केन्द्र।

कोराम्बे वाली टोंगरी के पास प्राचीन किले के अवशेष, पुरातत्वविदों के अनुसार यहाँ पर खुदाई से इतिहास के महत्वपूर्ण रहस्य खुल सकते हैं।

'सफलता शारीरिक शक्ति से नहीं वरन् अगम्य इच्छा शक्ति से आती है' - गाँधी जी

ग्रामीण विकास के विभिन्न योजनाओं का प्रतिवेदन सारांश

जिला – लोहरदगा (राशि लाख में) वर्ष 2006-07 माह – जुलाई 2006

क्रमांक	योजना का नाम	वित्तीय प्रतिवेदन								भौतिक प्रतिवेदन						
		1.04.06 को अवशेष राशि	2006-07 में प्राप्त आवंटन		अन्य स्रोत से/सूद	कुल उपलब्ध राशि	कुल व्यय की गई राशि	अवशेष राशि	प्रतिशत	1.04.06 को अपूर्ण योजना की संख्या	चालू वर्ष में ली गई योजना	कुल योजना	कुल पूर्ण योजना	अपूर्ण योजना	प्रतिशत	सृजित मानव दिवस
			केन्द्रांश	राज्यांश												
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
1	NREGA	1347.373	1843.350	202.378	0	3393.690	1384.553	2009.140	40.80%	2009	2963	4972	2226	2746	44.77%	11.651
2	SGSY	1.024	26.720	8.910	-	36.654	S 13.158 1.22.205 T 34.455	-32.356	33.42%	-	-				चयनित एस०एच०जी० की संख्या - 10	
3	IAY(New)	55.769	91.848	0.000	-	147.617	27.923	119.694	18.89%	190	350	540	167	373	30.93%	
4	Upgradation (IAY)	12.795	22.760	0.000	-	35.555	6.797	28.758	19.12%	89	168	257	54	203	21.01%	
5	Credit-Cum-Subsidy Scheme	17.726	0.000	0.000	-	17.726	0.000	17.726	0.00%	61	-	61	0	61	0.00%	
6	PMGY RH New	2.226	0.000	0.000	-	2.226	0.739	1.487	33.20%	14	-	14	4	10	28.57%	
7	Upgrad-PMGY RH	1.356	0.000	0.000	-	1.356	0.112	1.244	8.26%	17	-	17	6	11	35.29%	
8	Din Dayal Awas Yojana	233.47	0.000	5.702	-	209.172	113.127	96.045	54.08%	1819	-	1819	1348	471	74.11%	
9	Heriyali	19.094	0.000	0.000	-	19.094	15.959	3.135	83.58%	12	-	12	-	12	0.00%	
10	District Plan Untied Funds Scheme	22.464	0.000	0.000	-	22.464	2.000	20.464	8.90%	6	-	6	-	6	0.00%	
11	MLA Scheme	114.965	0.000	185.000	-	299.965	39.300	260.665	13.10%	94	16	110	52	58	47.27%	
12	MLA (Jal Samridhi)	44.985	0.000	65.000	-	109.985	42.720	67.265	38.84%	7	13	20	-	20	0.00%	
13	MPLADS	108.748	100.000	0.000	-	208.748	51.050	157.698	24.46%	36	82	118	37	81	31.36%	
14	Mid Day Meals	164.563	0.000	0.000	-	247.000	165.898	81.102	67.17%	सरकारी विद्यालय - 508/ उत्क्रमित विद्यालय - 11/ अपग्रेड विद्यालय - 309 * कुल 828 विद्यालय						
15	RSVY	575.181	0.000	0.000	-	575.181	559.596	15.585	97.29%	310	1283	1593	656	937	41.18%	